

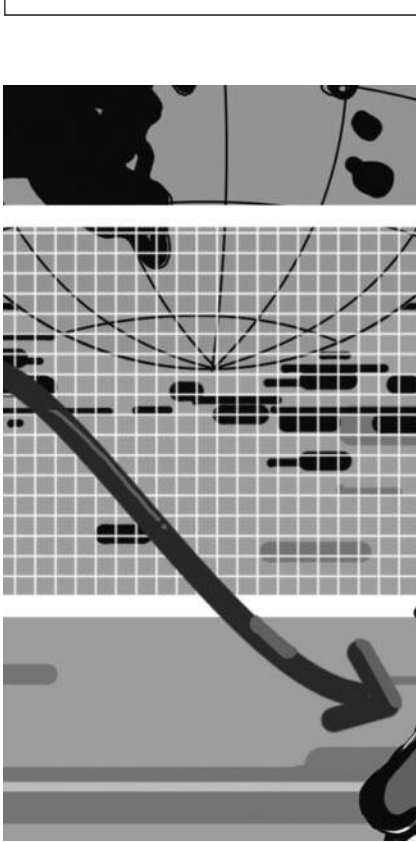
बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 214

दूरसंचार को एक और झटका

सर्वोच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत देश की शीर्ष दूरसंचार कंपनियों तथा सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर एक व्यवस्था दी है।

इसका संबंध कंपनियों द्वारा चुकाए जाने वाले शुल्क की प्रकृति से है। अदालत ने सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा है।



अजय मोहंती

वैश्विक निवेशकों से बातचीत का हासिल

यदि वृद्धि और सुधार के एजेंडे पर ध्यान दिया जाए तो भारत के पास यह अवसर है कि वह चीन की धीमी पड़ती आर्थिक गतिविधियों का लाभ ले सके। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं आकाश प्रकाश

पिछले दिनों मुझे अमेरिका में एक सप्ताह बिताने का अवसर मिला। वहां मैंने सम्मेलनों में हिस्सा लिया और वैश्विक फंड आवंटकों से मुलाकात की। निवेशकों से मुलाकात के लिए यह समय दिलचस्प था। भारत ने हाल ही में कर दरों में कटौती की थी और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आरंभ था। इस यात्रा का हासिल इस प्रकार रहा।

1. भारत को लेकर गहरी रुचि देखने को मिली और लोग यहां के हालात को समझना चाहते थे। ज्यादातर लोग कर कटौती से चकित थे क्योंकि उन्हें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह सवाल भी उठा कि कॉर्पोरेशन कर दर में कटौती क्यों की गई, मांग बढ़ाने के अन्य उपाय क्यों नहीं अपनाए गए। ज्यादातर लोगों की जिज्ञासा थी कि मध्य वर्ग के लिए कर कटौती या कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर का कटौती क्यों नहीं की गई? भारत को बड़ी और उच्च मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुकूल नहीं माना जाता जबकि वही इस कटौती से लाभान्वित हुईं। कुछ लोगों ने पूछा कि कंपनियां कर कटौती का प्रयोग कर नकदी प्रवाह कैसे बढ़ाएंगी? अमेरिका में ज्यादा

कानाफूसी

फिल्मी रास्ता

मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के एक छोटे से कस्बे चंदेरी (साड़ियों के लिए मशहूर) में पर्यटकों की बढ़ती तादाद से उत्साहित मध्य प्रदेश सरकार नई फिल्म नीति लाने की योजना बना रही है ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। यह विचार तब आया जब बॉलीवुड फिल्म स्त्री की कहानी के चंदेरी में केंद्रित होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की तादाद 50,000 का आंकड़ा पार कर गई। फिल्म स्त्री का काफी हिट हुई थी और कम बजट में बनी इस फिल्म ने काफी कमाई भी की थी। अधिकारियों का मानना है कि अगर एक फिल्म से क्षेत्र विशेष के पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ सकती है तो इसे बढ़ावा देना आवश्यक है। अब सरकार ने एक समन्वयक की नियुक्ति की योजना बनाई है जो प्रदेश में शूटिंग के लिए आने वाली फिल्म यूनिट का ध्यान रखेगा और उन्हें फिल्मांकन के लिए जगहों के सुझाव भी देगा।

दुविधा निवारक थिंक टैंक

स्वतंत्रता आंदोलन में विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका, अनुच्छेद 370 और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस स्वयं की दुविधा में पा रही है। ऐसे में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन विषयों पर आंतरिक चर्चा के लिए एक थिंक टैंक का गठन किया है। इस 17 सदस्यीय थिंक टैंक की पहली बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। इस दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी चर्चा होगी। सोनिया और उनके पुत्र राहुल गांधी के अलावा इस थिंक टैंक में शामिल अन्य नेताओं में मनमोहन सिंह,, ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राजीव गौड़ा, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, राजीव साठव और सुष्मिता देव भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस थिंक टैंक में शामिल नहीं हैं।



शामिल किया जाना चाहिए। यह अतिरिक्त बकाया करीब 23,000 करोड़ रुपये है। सरकार ब्याज, जुर्माना और जुमाने पर ब्याज की मांग भी कर रही है। यह राशि कुल मिलाकर 92,000 करोड़ रुपये हो जाती है। सरकार इस निर्णय से प्रसन्न होगी और राहत महसूस कर रही होगी क्योंकि अतिरिक्त राशि की मदद से उसे अपनी संकट वित्तीय स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। दरअसल इसमें से कुछ राशि का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की सरकारी प्रतिस्पर्धियों बीएसएनएल-एमटीएनएल की स्थिति सुधारने में भी किया जा सकता है।

दूसरी तरह से देखें तो यदि सरकार न्यायालय द्वारा दिए गए विकल्प को अपनाती

स्मॉल कैप 40 फीसदी। बाजार के बड़े हिस्से को फिलहाल निवेश योग्य नहीं माना जा रहा। चुनिंदा शेयरों के मूल्य को क्षति पहुंची है। कई शेयर खरीद न होने के कारण नुकसान में हैं। यदि वैश्विक आवंटकों को यह यकीन दिलाया जा सका कि वे शीर्ष 50 कंपनियों से परे निवेश करें तो भारतीय बाजार का मूल्य ठीकठाक है। उस स्थिति में काफी धन आ सकता है।

5. देश के कारोबारी प्रशासन को लेकर निराशा का माहौल था। कई लोग प्रवर्तकों की धोखाधड़ी और बैलेंस शीट की अनियमितताओं को लेकर स्तब्ध थे। वित्तीय सेवा क्षेत्र के कई खुलासे चिंतित करने वाले हैं। आखिर अंकेक्षक, रेटिंग एजेंसियां और नियामक क्या कर रहे थे? ऐसे खुलासे सामने आते रहे तो दिक्कत बढ़ेगी। शेयरों को गिरवी रखने का पैमाना देखकर निवेश चकित थे। कई लोगों ने कहा कि इस संचालन स्तर के साथ भारत महंगे उभरते बाजारों में शामिल नहीं हो सकता।

6. कई आवंटक इस बात से परिचित थे कि भारत एक किस्म की सफाई प्रक्रिया से गुजर रहा है। कई कमजोर कंपनियां और प्रवर्तक समूहों को ढहने दिया जा रहा है। अधिकांश ने माना कि ऐसी सफाई शुरुआत में वृद्धि को धीमा करती है। बहरहाल, आगे चलकर वृद्धि में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अधिकांश ने माना कि बीते चार वर्ष में भारत कई आर्थिक झटके झेल चुका है। पहले नोटबंदी, फिर वस्तु एवं सेवा कर और आखिरकार एनबीएफसी संकट। अर्थव्यवस्था के पास सुधारने का अवसर ही नहीं था। आने वाले वर्षों में जरूर हालात सामान्य हो सकते हैं।

7. अधिकांश निवेशक एनबीएफसी संकट की तीव्रता से चकित थे। यह भारत के लिए लीमन ब्रदर्स का ही एक छोटा रूप था। इस संकट ने इस क्षेत्र के अधिकांश थोक कारोबारियों के कारोबारी मॉडल को ध्वस्त कर दिया। अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भरोसे की कमी को देखते हुए आवंटकों को लगा कि आरबीआई को निवेशकों को एनबीएफसी के बहीखातों को लेकर आश्वस्त करना चाहिए था। इससे निवेशकों को काफी मदद मिलती। निजी पूंजी जुटने से ही माहौल में सुधार होगा। निजी पूंजी को रेटिंग एजेंसियां या अंकेक्षकों पर भरोसा नहीं। केवल आरबीआई ही इस गतिरोध को दूर कर सकता है।

8. अधिकांश आवंटकों को यकीन था कि चीन और अमेरिका का तनाव आगे भी बरकरार रहेगा। परिणामस्वरूप चीन में धीमापन आएगा और उसकी अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर देख चुकी है। अधिकांश आवंटक चीन से इतर एशिया के अन्य हिस्सों में अपना निवेश बढ़ाना चाहते थे।

भारत के पास अवसर है कि वह आने वाले वर्ष में निवेश आकर्षित कर सके। निवेशक समझ रहे हैं कि वृद्धि और आय दोनों एकदम निचले स्तर पर हैं। आवंटक धीमी विश्व व्यवस्था में वृद्धि की बात जोह रहे हैं। अधिकांश लोग अभी भी मानते हैं कि लंबी अवधि में देश के पास काफी संभावनाएं हैं। अगर हम स्थिर रहे तो हम लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

है तो यह दूरसंचार बाजार पर प्राणांतक वार की तरह होगा। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में भारती एयरटेल पर करीब 1.06 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कुछ लॉबित स्पेक्ट्रम भुगतान इससे इतर था। इस राशि का आधा हिस्सा अल्पावधि की जवाबदेही था। इसी अवधि में वोडाफोन आइडिया पर कुल 1.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह अतिरिक्त बोझ ऐसे वक्त में आया है जब ये कंपनियां रिलायंस जियो के साथ कीमतों की जंग में उलझी हुई हैं। जियो अपनी सेवाएं घाटे पर देने को तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के पास रिलायंस समूह के पेट्रोलैमिकल व्यवसाय से काफी धन आ रहा है। सरकार को अब यह निर्णय लेना है कि आगे क्या राह है।

दो दशक में भारतीय समाज और राजनीति हो गई ज्यादा संकीर्ण

बीस वर्ष पहले सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एक भारतीय अमर्त्य सेन को मिला था। इस वर्ष एक अन्य भारतवंशी अभिजित बनर्जी को यह सम्मान मिला है। दोनों घटनाओं में दो दशक का अंतराल है लेकिन ऐसा लगता है कि आज का भारत उस वक्त से एकदम अलग है। इस अंतर को दोनों विजेताओं को सम्मानित किए जाने पर सत्ता प्रतिष्ठाान की प्रतिक्रिया से भी समझा जा सकता है। खासतौर पर सत्ताधारी दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बनर्जी को पुरस्कार मिलने पर जो प्रतिक्रिया दी है उससे यह स्पष्ट होता है।

सन 1998 में सेन को सम्मानित करने के नोबेल समिति के निर्णय के बाद चौतरफा सराहना का भाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने सेन को दिए संदेश में कहा था कि यह बेहद नेकनीयत से दिया गया है और उन्होंने कहा कि वह कामना करते हैं कि सेन आगे लंबे समय तक बेहतर अकादमिक और शोध कार्य करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने संदेश में कहा कि उन्हें यह सम्मान मिलना राष्ट्रीय गौरव का विषय है। वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी सेन की तारीफ की।

यकीनन बनर्जी को इस वर्ष नोबेल मिलने के बाद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति ने कहा कि बनर्जी के काम ने तमाम अर्थशास्त्रियों को भारत तथा विश्व में गरीबी से लड़ने की बेहतर समझ दी है। मोदी ने गरीबी उन्मूलन में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें बधाई दी। सीतारमण ने भी बनर्जी को के दर्शन से अलग था। वाजपेयी वैश्विक दृष्टि को लेकर चलते थे। उनकी सरकार आज की तुलना में अधिक समावेशी और सहिष्णु थी। वित्त के तब तक कि वाजपेयी सरकार के प्रमुख सदस्यों में से एक मुरली मनोहर जोशी ने भी बिना किसी पूर्वग्रह के सेन को बधाई दी थी। ऐसा तब था जबकि सेन उस राजनीतिक फलक से आते थे जिससे उन्हें या उनकी पार्टी को कोई सहायुभूति नहीं थी।



ए के भट्टाचार्य

की ओर था जिसे बनर्जी का समर्थन मिला था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश सिन्हा ने भी बनर्जी के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसकी तुलना सेन से करते हैं। सेन को पुरस्कार मिलने के कुछ ही दिन के भीतर सरकारी विमानन सेवा एयर इंडिया ने जीवन भर की यात्राओं के लिए निःशुल्क पास की पेशकश कर दी थी। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों वित्त सचिव विजय केलकर और मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर एन आचार्य ने उनकी जमकर सराहना की और बधाई दी। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी सेन को बधाई दी थी। संक्षेप में कहें तो सन 1998 में 2019 की तरह कोई आलोचना सुनने को नहीं मिली थी।

बीते दो दशक में क्या बदला? सन 1998 में भी भाजपा की सरकार थी और 2019 में भी वही सत्ता में है। सन 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को मोदी की तरह बहुमत हासिल नहीं था। संभव है कि वाजपेयी की सरकार गठबंधन साझेदारों पर बहुत हद तक निर्भर थी। मोदी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। दिलचस्प यह है कि वाजपेयी सरकार का दर्शन भी आज की मोदी सरकार के दर्शन से अलग था। वाजपेयी वैश्विक दृष्टि को लेकर चलते थे। उनकी सरकार आज की तुलना में अधिक समावेशी और सहिष्णु थी। वित्त के तब तक कि वाजपेयी सरकार के प्रमुख सदस्यों में से एक मुरली मनोहर जोशी ने भी बिना किसी पूर्वग्रह के सेन को बधाई दी थी। ऐसा तब था जबकि सेन उस राजनीतिक फलक से आते थे जिससे उन्हें या उनकी पार्टी को कोई सहायुभूति नहीं थी।



विदेश भाग जाते हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या का उदाहरण हमारे सामने है। हाल में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले ने लोगों को फिर सोचने पर मजबूर किया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रिजर्व बैंक ठीक से निगरानी क्यों नहीं रख पाता है। सवाल यह है कि अनियमितताएं वर्षों तक ऑडिटर की नजर से कैसे

बच जाती है। ऑडिट रिपोर्ट राजनीतिक हस्तक्षेप से भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में निगरानी करने वाली संस्था का ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली होना जरूरी है। बैंकों

में कठोर प्रक्रिया और नियमों का पालन सुनिश्चित कर बड़े घोटाले से बचा जा सकता है। बैंकों की नियामक संस्था रिजर्व बैंक के साथ वित्त मंत्रालय की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह बैंकों में अनियमितता और कुप्रबंधन को ठीक करने के लिए अपने स्तर पर समय – समय पर उचित कदम उठाए। जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें पैसों की दिक्कत नहीं हो और उन्हें आसानी से कर्ज दिया जाए। यह सरकार की अच्छी सोच है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। अगर उद्योग–धंधे बढ़ होंगे तो इससे लोग बेरोजगार होंगे और अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऋण की स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

राजीव सिंह, हैदराबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

और निवेश को प्राथमिकता देकर इस क्षेत्र की उत्पादकता और वृद्धि में सुधार किया जा सकता है तो उसे अलग तरीके से सोचना होगा। कंपनियों को जल्दी ही 5जी के बुनियादी ढांचे में निवेश आरंभ करना होगा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल भारत का अपना लक्ष्य हासिल करना है तो संचार क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के इर्दगिर्द एक नवाचारी व्यवस्था आरंभ करनी होगी। सरकार की मांग से पहले ही त्रस्त यह क्षेत्र इस बुनियादी ढांचे को आकार देने में सक्षम नहीं है।

अब यह निर्णय सरकार को लेना है कि उसे इस क्षेत्र के साथ कैसा व्यवहार करना है। संभव है वह व्यापक राष्ट्रीय हित को देखते हुए जुर्माना और ब्याज माफ कर दे।

इसके विपरीत मोदी सरकार अपनी राजनीतिक मान्यताओं को लेकर काफी आक्रामक है। वाजपेयी सरकार के उलट मोदी सरकार और उसके वरिष्ठ सदस्यों का रुख बहुसंख्यकवादी है। वे अपने प्रतिकूल विचारों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसे में मोदी ने तो नोबेल विजेता को बधाई दी लेकिन उनकी पार्टी या सरकार के सदस्यों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करना या विपक्षी दल को मशविरा देने के लिए उनकी आलोचना करना बंद नहीं किया।

बहरहाल बनर्जी ने बाद में कहा कि वह सिर्फ एक पेशेवर अर्थशास्त्री हैं और संपर्क करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को मशविरा देते हैं। वह कई ऐसी राज्य सरकारों के साथ भी काम कर रहे हैं जो भाजपा शासित हैं। ऐसा नहीं है कि इन सरकारों की वजह से उन्होंने पेशेवर सेवाएं देने से मना किया हो।

बीते दो दशकों में न केवल भारतीय समाज और राजनीति में बदलाव आया है बल्कि ये अधिक संकीर्ण भी हुए हैं। इस दौरान अर्थशास्त्रियों में भी काफी बदलाव आया है। सन 1998 में जब अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था तब देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी टिप्पणी थोड़ी बंधी हुई थी। ऐसी टिप्पणी के बारे में माना जा सकता है कि वह सत्ताधारी दल की प्राथमिकताओं या चिंताओं को लेकर अनिवार्यक शर्मिंदगी न उत्पन्न करे। बीते दो दशक में यह बदला है। आज के अर्थशास्त्री पहले वालों से कहीं अधिक निश्चित हैं और वे ऐसी टिप्पणियां करने से घबराते नहीं हैं जो उनके देश की सरकारों को नाखुश कर दें।

यही कारण है कि रघुराम राजन हों, अरविंद सुब्रमण्यन हों या अभिजित बनर्जी, इन सभी ने खुलकर अपनी बात कही। इनके मन में ऐसी कोई चिंता नहीं थी कि उनके नजरिये से सरकार शर्मिंदा हो सकती है। परंतु सरकार द्वारा ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों को हजम कर पाना हालात को अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाता है। जबकि उसे विचार यह करना चाहिए कि क्या इससे नीति निर्माण में कोई लाभ हो सकता है। यह दुखद है कि सरकार अब तक इस कमजोरी को समझ नहीं पाई है न ही वह आवश्यक संशोधन कर रही है।

गरीबों को मिला आयुष्मान का लाभ

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। आयुष्मान योजना को सफल बनाने में निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग की भी जरूरत है। चिकित्सा पर होने वाले खर्च की वजह से कई लोग अपना कीमती सामान गिरवी रखने से बचे हैं। इसे आयुष्मान भारत की बड़ी सफलता माना जा सकता है। देश के लाखों गरीबों के बीच बीमारियों से मुक्त होने की उम्मीद जगाना भी बड़ी उपलब्धि है। यह सभी नागरिकों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्रीय बिंदु है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर काफी जोर दिया है और इस योजना को शहर से लेकर गांव तक पहुंचाया गया है।

दिवाकर कुमार, मधुपुर